THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (SHRI B. SHANKARANAND): (a) and (b) The Government of Meghalaya have proposed to take up Rongai Valley Irrigation Scheme in the VII Five Year Plan to provide irigation fatilities to an area of 4760 hectares in Garo Hills District. The State Government has sought the Expert assistance of Central Water Commission for carrying out the necessary detailed field investigations and for collection of requisite hydrological data for firming up the proposals. External financial assistance is not envisaged for this scheme.

Power projects in the North-Eastern Region

132. SHRI JERLIE E. TARIANG: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that power projects in the North Eastern Region need immediate renovation and modernisation for generating increased power; and

(b) whether Government propose to take up this work during the Seventh Plan period?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER (SHRI ARUN NEHRU): (a) and (b) The Assam State Electricity Board had submitted a project report for the renovation and modernisation of the Namrup Thermal Power Station. The Central Electricity Authority has accorded techno-economic approval to the Scheme in March, 1985. No other renovation and modernisation scheme from the North-Eastern region has been received in the Central Electricity Authority.

Request of Rajasthan Government for generating power in the joint sector

133. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether the Rajasthan Government has sought the permission of the Central Government to generate power in the joint sector;

(b) if so, the broad outlines of the projects forwarded to the Centre for clearance;

(c) the stage at which the matter stands at present; and

(d) whether the Rajasthan Government has also asked for raising the capacity of the gas-based power plant to be put at Kotah to 500 MW and if so, the Central Government's decision in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER (SHRI ARUN NEHRU): (a) to (c) The Rajasthan State Electricity Board have forwarded to the Central Electricity Authority a project report for installing 2x210 MW capacity at Dholpur, at a revised estimated cost of Rs. 648.11 crores. Subsequently, the State Government suggested implementation of the project in the joint sector with I.D.B.I. assistance. It has been suggested to the State Government that the matter regarding availability of IDBI assistance may be pursued with the Ministry of Finance. The CEA can appraise the project report for techno-economic approval after necessary inputs such as availability of coal and water and environmental clearance etc. have been tied up.

(d) The Rajasthan Government have also suggested that the capacity of the proposed gas based thermal plant in the State may be raised to 500 MW. It has been intimated to the State Government that the capacity of the power station will be gover-

ned by the technical considerations, including the availability of gas and other infrastructural facilities.

मैक्सिको में आयोजित विश्व जनसंख्या सम्मेलन

134. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 अगस्त, 1985 को मैक्सिको शहर में आयोजित विश्व जनसंख्या सम्मेलन में साधारण शिक्षा, विशेषत: महिला शिक्षा और सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के समुचित प्रचार और विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किए गये प्रस्ताव को मूर्त रूप देने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) अगस्त, 1984 में मैक्सिको सिटी में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय जनसंख्या सम्मेलन में महिलाओं की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अन्तर्गत जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया था । इसमें उन देशों से भी, जहां अभी भी बहुत-सी अशिक्षित महिलायें हैं, जन शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए पूरक प्रयास करने का अनुरोध किया गया था । ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को समग्र स्वास्थ्य परिचर्या के अंग के रूप में जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना में सुदृढ़ किया जा रहा है। महिला साक्षरता की सुविधाओं को भी बढ़ाया जा रहा है।

स्कूलों और कालेजों में "सहकारिता" को एक विषय के रूप में शुरू किया जाना

135. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग में शिक्षा सलाहकार और स्कूलों और कालेजों में सहकारिता को एक विषय के रूप में किये जाने संबंधी समिति के अध्यक्ष, श्री डी०पी० नायर ने 1978 के आरम्भ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था और उसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि देश के नागरिकों को सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाने और छात्र समुदाय के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के वास्ते स्कूलों में सहकारिता को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिये, यदि हां, तो उनके द्वारा दिये गए सुझावों का ब्यौरा क्या है, जिससे कि इस विषय को लोकप्रिय बनाया जा सके सके;

(ख) सरकार ने किस प्रकार सहकारिता के बारे में सैद्धांतिक और व्यावहारिक पाठ्यक्रम तैयार किये है; किन-किन राज्यों में इन पाठ्यक्रमों को शुरू कर दिया गया है और शेष राज्यों में इस विषय को शुरू करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है;

(ग) क्या यह सच है कि यह मामला 107 विश्वविद्यालयों को उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए भेजा गया था और उनमें से केवल 31 विश्वविद्यालयों ने उत्तर भेजे हैं, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस योजना को तेजी से लागू करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) 4-11-1975 को भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ की सहकारिता प्रशिक्षण समिति (जो अब राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद के नाम से जानी जाती